9 मई 2017 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के क्रम में आयोजित जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला प्रदर्शनी सह संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्ष का भाषण

1. तीन दिवसीय इस मेले से निश्चय ही किसान भाइयों व बहनों ने कृषि से संबंधित नई जानकारियां हासिल की होंगी। पारम्परिक खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी तो हमेशा से होती आई है और पहले के समय हर किसान को अपनी जमीन, अपने खेतों की प्रकृति की उतनी ही बारीकी से जानकारी होती है जैसे एक मां को अपनी संतान में विषय में।

2. खेतों की प्रकृति के अतिरिक्त उपज बढ़ाने के लिए कई नई जानकारियां आधुनिक खेती के लिए अपरिहार्य है। किसान सम्मेलन में यही नई एवं आवश्यक पहलुओं से किसान भाई रू–ब–रू होते हैं। आज के युग में विज्ञान व तकनीक ने हर क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन ला दिया है।

3. कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है बल्कि भारत का 70 प्रतिशत मध्यम व निम्न वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हमारे देश की नींव कृषि व किसान हैं। कृषि एक कला है, एक संयम, समर्पण एवं आधार भी है।

4. मध्यप्रदेश की जलवायु, परिस्थिति, मिट्टी व विविधता फसल के पैटर्न के साथ अलग–अलग और सम्पन्न हैं। काली मिट्टी की बहुलता वाले इस क्षेत्र में सोयाबीन, दलहन, कपास, मोटे अनाज एवं मक्का इत्यादि की अच्छी

खेती होती है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 7.7 प्रतिशत पैदावार यहीं से होती है और ये आप सब किसान भाइयों की मेहनत से ही संभव है।

5. मध्यप्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद की औसतन विकास दर पिछले एक दशक से लगभग 11.84 प्रतिशत रही है और यहां की आबादी के 74 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर हैं। आज की तारीख में मध्यप्रदेश भारत का सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक है। इस उपलब्धि के लिए यहां की सरकार और संस्थाओं के साथ–साथ आप सभी बधाई के पात्र हैं।

6. भारतीय कृषि जोखिम और अनिश्चितताओ के नये रूपों का सामना कर रही है। चूंकि आज के समय में जलवायु परिवर्तन से कृषि प्रभावित हो रही है जिससे नए माहौल के अनुकूल फसलों को विकास, बुवाई के समय में परिवर्तन आदि को अपनाने की आवश्यकता है।

7. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि ''ग्राम उदय से भारत उदय'' संभव है और इसी भावना के तहत जिला इन्दौर में 15 अप्रैल से 2 मई 2017 तक कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान जिले के समस्त 312 ग्राम पंचायतों में कृषि संबंधी जानकारियां किसानों को उपलब्ध कराई गईं।

8. सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कार्य किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता, सम्पूर्ण मूल्यांकन और गुणवत्ता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए Soil Health Card जारी करना है। यह वर्ष 2017 तक सरकार की योजना 14 करोड़ लोगों को Soil Health Card जारी करने की है। वर्तमान में लगभग 2 करोड़ Soil Health Card जारी किए जा चुके हैं।

9. हरित क्रांति के दौरान खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए खेतों में जो रासायनिक उर्वरक प्रयोग में लाए गए, उसके चलते खेतों की मिट्टी के साथ–साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। नतीजतन हमें जैविक खेती की ओर जाना पड़ रहा है। इससे न केवल खेतों की सेहत सुधर रही है और साथ–ही–साथ biodegradable waste का proper disposal हो रहा है। इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी मदद मिल रही है।

10. आज रेल, रोड, एयर नेटवर्क तेज गति से आगे बढ़ा है। पिछले दो सालों में प्रतिदिन लगभग 17.30 किलोमीटर की गति से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। वैसे ही अन्य योजनाओं से भी तेज गति से सड़कें बन रही हैं। शोध में यह पाया गया है कि 30 प्रतिशत उत्पादित फसलें गोदाम की कमी के कारण, ठीक से रख–रखाव नहीं किए जाने और मंडी में पहुंचने में हुई देरी से नष्ट हो जाते हैं। परिवहन तथा अन्य अनुषंगी

क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के कारण किसानों को अपने उत्पादों को मंडी एवं ग्राहक तक पहुंचाने में आसानी हो रही है और उन्हें बिक्री के लिए बड़ा बाजार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

11. अभी हाल ही में Inland waterways authority of India Bill पास हुआ है जिसके तहत देश के अन्दर निर्बाध जल मार्ग विकसित होगा। इन जलमार्गों का उपयोग भी सस्ते transportation cost पर किसानों के उत्पादों के आयात–निर्यात के लिए किया जा सकता है।

12. भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। जीएसटी एक्ट के लागू होने से Agricultural Supply Chain Mechanism में पारदर्शिता, स्थायित्व और विश्वास आएगा। बेहतर Supply Chain Mechanism से किसानों की फसल उत्पादन लागत और उत्पादों की बर्बादी दोनों में कमी आएगी और इससे किसानों के साथ–साथ ग्राहकों को भी बहुत फायदा होने वाला है।

13. सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक नया बाज़ार (E-National Agricultural Market) ई–नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट उपलब्ध कराया है, जो कि एक ई–कॉमर्स प्लेटफार्म है। इसके जीएसटी से जुड़ जाने से फसल उत्पादों एवं उससे बने सामानों की अतंर्राज्यीय आवाजाही में सुलभता होगी। फलतः, किसानों को अपने उत्पाद की सही

कीमत मिलेगी और साथ ही, उपभोक्ताओं को भी ताजा उत्पाद समय पर उपलब्ध हो सकेगा।

14. आज हम देखते हैं कि लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। परंतु कृषि सम्माननीय है और किसान भी। हमें यह समझना है और आगे की पीढ़ी को भी समझाना है। किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम कड़ी हैं। ग्रामीण और शहरी असमानता को दूर करने और ग्रामीण आजीविका विकल्पों में विविधता लाने के लिये, फसलों, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, floriculture, pissiculture, poultry farming और मशरूम पालन जैसी नई आर्थिक गतिविधियों में भी किसान भाईयों–बहनों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

15. एक अनुमान के मुताबिक सन् 2050 तक विश्व की 80 प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्रों में रहने लगेंगी और तबतक आज की जनसंख्या में लगभग 300 करोड़ की वृद्धि होगी। अतः, उनके रहने एवं अन्य अवसरंचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे भूमि का एक बड़ा हिस्सा इस कार्य के लिए उपयोग में आ जाएगा। अभी ही जापान जैसे कुछ देशों में वर्टिकल फार्मिंग (Vertical Farming) का प्रयोग किया जा रहा है। जमीन के कम हिस्से में पार्किंग की तरह multi storey and multi layer structures बनाकर उसका इस्तेमाल Vertical Farming हेतु किया जा रहा है। यह आवासीय क्षेत्रों में और छत के ऊपर किया जा रहा है।

16. कृषि के लिए जल का संग्रहण, उसका बेहतर प्रबंधन एवं उपयोग सुनिश्चित करना भी बहुत आवश्यक है। जल संग्रह एवं उनके बेहतर उपयोग की ओर नागरिकों विशेषकर किसान भाइयों के ध्यानाकर्षण से न केवल उनकी उपज में वृद्धि होगी बल्कि वाटर टेबल को restore करने और वनीकरण में भी मदद मिलेगी।

17. किसान प्रकृति के महत्व को जानते हैं कि उसके संरक्षण और संवर्धन में ही उनका लाभ है। मैं झारखंड के ओरमांझी ब्लॉक का एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहूंगी जिसमें किसानों ने किस प्रकार भूमि का सदुपयोग सुनिश्चित किया है। उन्होंने गांव के निकट खाली पड़ी जमीन पर आठ–आठ फीट के अन्तर पर बड़े वृक्ष लगाएं। दो वृक्षों के बीच के जगह में थोड़ा गड्ढा खोदकर उसमें उन्होंने अदरख एवं हल्दी जैसे पौधे लगाए। इस प्रकार, उन्हें एक साथ ही तीन फायदे हुए। प्रकृति का संरक्षण भी हुआ, जलस्तर भी बढ़ा और आर्थिक लाभ भी।

18. भोजन की बर्बादी एक बहुत गंभीर समस्या है। एक आकलन के अनुसार भारत में जितना भोजन एक दिन में नष्ट हो जाता है, वह ब्रिटेन की पूरी आबादी के एक दिन के भोजन के लगभग बराबर है। साथ ही, जितना भोजन भारत में एक दिन खाने के बाद जूठन के रूप में फेंका जाता है, उतने भोजन में जापान की पूरी आबादी भोजन कर लेगी। भारत में 40 प्रतिशत खाद्य उत्पाद नष्ट हो जाते हैं जिसका मूल्य लगभग प्रति

वर्ष 50,000 करोड़ रुपये है और विडम्बना यह है कि लगभग 20 करोड़ लोग किसी एक दिन भोजन के अभाव के भूखे पेट सो जाते हैं।

19. एक आंकड़े के अनुसार, 1 किलो चावल उपजाने में लगभग 2500 लीटर से लेकर 3400 लीटर पानी का उपयोग होता है जबकि 1 किलो चीनी उपजाने में लगभग 1500 से 2000 लीटर पानी का उपयोग होता है, जबकि 1 किलो कपास उपजाने में 10000 लीटर पानी लगता है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमें भोजन की बर्बादी रोकने के लिए गंभीरता से कदम उठाने होंगे।

20. देश में कृषि उत्पादन की अपार संभावना होने के बावजूद हम एक समय अनाज के सबसे बड़े आयातकों में से एक थे। दुनिया के कृषि उत्पादन में हमारा योगदान विविध है। हम चाय, जूट, गन्ना और काजू के शीर्ष उत्पादक रहे हैं। फिर भी हमारे ज्यादातर किसान खेती के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। यदि मानसून अच्छा न हो, तो आज भी वे संकट में पड़ जाते हैं। इन परिस्थितियों में सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण करके किसानों को हर तरह की मदद प्रदान करना सरकार के महत्वपूर्ण कर्त्तव्यों में से एक होना चाहिए।

21. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) लागू की गई। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 12.7 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि पर अधिक

फसल और हर खेत को पानी उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

22. सरकार ने कृषि के समग्र विकास के लिए ऐसे कई और कदम उठाए हैं। जैसे संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना विकसित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (The Commission for Agricultural Costs and Prices) का गठन किया गया था। किसानों को छोटे ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जोखिम–कवरेज के दायरे का विस्तार करने एवं बीमा राशि को दोगुना के लिए नई फसल बीमा योजना को कार्यान्वित किया गया। किसान भाई इन योजनाओं का ज्यादा–से–ज्यादा लाभ उठाएं।

23. सरकार ने किसानों की आय वर्ष 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा है इस दिशा में वह हरसंभव प्रयास कर रही है। आज सरकार की नीति देश के नागरिकों को food security उपलब्ध कराने के साथ–साथ किसानों को सुनिश्चित आय (income security of the farmers) प्रदान करने की है। अब कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय हो गया है।

24. मैं इंदौर कृषि महाविद्यालय में किसान मेला के सफल आयोजन के लिए आयोजकों, प्रतिभागियों, किसानों और अन्य लाभार्थियों, सभी को बधाई देती हूं। इसको सफल बनाने में संबंधित कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों

एवं संस्थाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने यहां आकर अपने कृषि संबंधी ज्ञान और अनुभव में वृद्धि की, उसका लाभ आप अपने संबंधित कृषि कार्य के साथ–साथ आपके साथी किसानों को भी मिलेगा। एक बार पुनः आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं।

जय हिन्द।

–––––